

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 132/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम बालोतरा जरिये कार्यकारी सदस्य श्री करनाराम पुत्र श्री केसाराम जाति वाल्मिकी निवासी बालोतरा		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा। 2. नायब तहसीलदार जसोल।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 05.01.2023

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट ग्राम बालोतरा की खसरा संख्या 572 की भूमि में अवस्थित है, खसरा संख्या 572 पूर्व में रूपाराम पुत्र गणेशराम व श्रीमति गेती देवी पत्नि रूपाराम जाति माली निवासी बालोतरा के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि रही है। जिनके द्वारा उक्त भूमि काफी वर्षों पूर्व अपनी स्वैच्छा से वाल्मिकी समाज बालोतरा को भेंट की गई। वक्त भेंट से आदिनांक तक वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट का बिना दखल हस्तक्षेप उपयोग, उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है, और न उक्त भूखंड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या

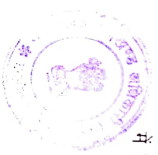


*(Signature)*  
5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



संख्या 529,747,870,950.1106.1741/982 कुल रकबा 1753.14 बीघा पर तथाकथित अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन संख्या 544/2020 प्रस्तुत की गई जिस पर प्रार्थी द्वारा D.B Civil INTERLOCUTORY APPLICATION NO. 24/2020 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय को आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट खसरा संख्या 572 में अवस्थित है, खसरा संख्या 572 पूर्व में रूपाराम पुत्र गणेशराम व श्रीमति गेती देवी पतिन रूपाराम जाति माली निवासी बालोतरा के खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि रही है। जिनके द्वारा उक्त भूमि काफ़ी वर्षों पूर्व अपनी स्वैच्छा से वाल्मिकी समाज बालोतरा को भेंट की गई। वक्त भेंट से आदिनांक तक वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट का बिना दखल हस्तक्षेप उपयोग/उपभोग में लिया जा रहा है। उक्त भूखंड लूणी नदी के सीमा के भीतर नहीं है और न उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरा संख्या 529,747,870,950.1106.1741/982 के भाग पर अतिक्रमण/अवरोध ही किया है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकात्मका सीमांकन करते हुए प्रार्थी के भूखण्ड को गैर मुम्किन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी का श्मसान गृह परिसर वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 572 में अवस्थित है। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वे में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित भूखण्ड श्मसान गृह परिसर को गै.मु.नदी में रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, जो कि अदिनांक तक रेकर्ड व नक्शा में विवादित भूमि का गलत अंकन इन्द्राज होता आ रहा है जो कि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि में होने के कारण रेकर्ड व राजस्व नक्शा टुकरी योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया कि प्रार्थी का परिसर श्मसान घाट खसरा संख्या 572 में अवस्थित होने के उपरान्त भी गैर-मुम्किन नदी में दर्शा दिया गया। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के

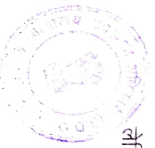


*Pravraj*  
5.1.2023  
भूखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

हितवद् पक्षकारण को विना सुनवाई के अवसर दिये खातेदारी स्थापित भूमि होने के उपरान्त भी विवादित शमसान घाट को गैर मुमकिन नदी में इन्द्राज कर दी थी, जो कि सरासर गलत तथ्यों के आधार पर रेकॉर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम शमसान घाट परिसर को खसरा संख्या 572 भूमि का भाग मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शों में तरसीम दुरुस्ती करवाने का आदेश प्रमाया जावे।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी को बहस है, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेंट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेंट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करावाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम शमसान घाट परिसर गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। विवादित भूखण्ड खसरा संख्या 572 में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौरान कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो।

लोकित्त हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेंट के



विप्रार्थी  
5.1.2023

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोत्तर

अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितवद्द पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संभारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गैमु नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजरव अभिलेख व नवशा लवड़ा में तरगीम दुरुस्त करवाने की फ़िराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज होना बता रहे है, गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 293 गैर मुमकिन नदी है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 1741 / 982 गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन-पत्र साहरीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।


7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजरव रेकर्ड मय दरतावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है कि प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर खसरा संख्या 572 में स्थित है, मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी के परिसर के आस-पास बने हुए निर्मित परिसर भी नगरपालिका की भूमि में है। लेकिन प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट नगरपालिका की भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजरव अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर नगरपालिका भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरगीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्वॉज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट को खसरा संख्या 572 भूमि में होना मानकर राजरव अभिलेख व नक्शों में तरगीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर वाल्मिकी समाज मुक्तिधाम श्मसान घाट परिसर



5.1.2023  
S.D.O. Bahawalpur

होना बता रहा है, वह गत सेटलमेंट अनुसार भी खसरा नम्बर 293 किस गैर मुमकिन नदी में आता है, इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेंट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेंट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड संधारण किया था, जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है कि प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकॉर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्दाज है। प्रथम सेटलमेंट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेंट भी हो चुका है। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकॉर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस विन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर नगरपालिका बालोतरा के खसरा नम्बर 572 में है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये हैं, कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर नगर परिषद खसरा संख्या 572 भूमि में आती है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। तहसीलदार पंचपदरा की रिपोर्ट अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में भूप्रबंध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर वाइमेर के आदेश क्रमांक/प./14/(28)(1)/भूअ.। रा.प्र./2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भूप्रबंध विभाग कि संयुक्त टीम गठित कर गत भूप्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 293 का



  
5.1.2023  
राजस्व एवं भू प्रबंध विभाग  
(S.D.O.) ललौतरा

भाग होना बताया गया है, जो तत्समय प्रचलित भूपत्र के रैकर्ड के अनुसार गैर-मुम्किन नदी थी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी वालिका समाज मुक्तिधाम श्रमस्थान घाट परिसर गैर-मुम्किन नदी का ही भाग है। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निर्धार पर पहुंची है कि आवेदन-पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दरतावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरसीम दुरस्ती योग्य है। ऐसी सूत्र में प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।



आदेश आज दिनांक 05.1.2022 को लिखा जाकर सर्रे इजलास सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*

(विवेक ब्यास)

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

*(Handwritten signature)*  
05.1.2022

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा